eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का पुनर्गठन: ताइवान जलडमरूमध्य संकट के संदर्भ में भारत की भू–रणनीतिक वास्तुकला, डिजिटल संप्रभुता, और भारत–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

मुकेश कुमार पाण्डेय[1], प्रो0 ए0 पी0 सिंह[2]
[1]शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग, एस0 एम0 कॉलेज, चंदौसी
[2]शोध निर्देशक राजनीति विज्ञान विभाग, एस0 एम0 कॉलेज, चंदौसी उ0प्र0 (सम्बद्ध: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली)

Received: 26 Dec 2025 Accepted & Reviewed: 28 Dec 2025, Published: 31 December 2025

Abstract

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति–संतुलन का पुनर्गठन तीव्र होता जा रहा है, जहाँ महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, समुद्री भू–राजनीति और डिजिटल अवसंरचना का रणनीतिक महत्व निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यह शोधपत्र ताइवान जलडमरूमध्य संकट की पृष्ठभूमि में हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत की उभरती भू–रणनीतिक संरचना का विश्लेषण करता है, जो वैश्विक आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा आयामों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अध्ययन का तर्क है कि समकालीन भू–राजनीति अब केवल भू–क्षेत्रीय नियंत्रण तक सीमित नहीं रही, बल्कि समुद्री मार्गों, डेटा प्रवाह, आपूर्ति शृंखलाओं और डिजिटल संपर्कता के शासन द्वारा संचालित हो रही है। इसमें चीन के समुद्री विस्तारवाद, बेल्ट एंड रोड पहल और डिजिटल प्रभाव के माध्यम से क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन में आए परिवर्तनों तथा भारत–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की गहनता का विश्लेषण किया गया है। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने समुद्री संतुलन, डिजिटल संप्रभुता, रणनीतिक साझेदारियों और मुद्दा–आधारित बहुपक्षवाद को अपनाते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि रणनीतिक लचीलापन भारत को नियम–आधारित, समावेशी और स्थिर हिंद–प्रशांत व्यवस्था में एक स्थिरीकरणकारी शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

मुख्य शब्द – हिंद–प्रशांत, ताइवान जलडमरूमध्य, भारत–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, समुद्री भू–राजनीति, डिजिटल संप्रभुता, रणनीतिक स्वायत्तता

Introduction

हिंद–प्रशांत इक्कीसवीं सदी में वैश्विक शक्ति के पुनर्गठन के मुख्य मंच के रूप में उभरा है, जहाँ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा समुद्री, डिजिटल, आर्थिक और भू–राजनीतिक क्षेत्रों में तेजी से फैल रही है। अफ्रीका के पूर्वी तटों से लेकर पश्चिमी प्रशांत तक फैले इस क्षेत्र में वैश्विक जीडीपी का 60 प्रतिशत से अधिक, वैश्विक व्यापार का लगभग 65 प्रतिशत और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, जो इसे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए अपरिहार्य बनाता है। इस बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य में, भारत काफी हद तक एक महाद्वीपीय शक्ति से एक निर्णायक समुद्री–डिजिटल खिलाड़ी के रूप में बदल गया है, जो बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच एक बहुध्रुवीय, नियम–आधारित व्यवस्था को आकार देना चाहता है। यह परिवर्तन भारत की हिंद–प्रशांत में उभरती भू–रणनीतिक वास्तुकला के रूप में देखा जा सकता है – एक बहु–स्तरीय ढाँचा जो डिजिटल संप्रभुता, समुद्री भू–राजनीति, रणनीतिक साझेदारी और ताइवान जलडमरूमध्य जैसे क्षेत्रीय संकटों के लिए मापी गई प्रतिक्रियाओं को जोड़ता है। हिंद–प्रशांत अब केवल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए एक मार्ग नहीं रह गया है; यह एक प्रतिस्पर्धी रणनीतिक स्थान बन गया है जहाँ समुद्री मार्गों, समुद्र के नीचे के बुनियादी ढाँचे, डेटा प्रवाह और भू–राजनीतिक कथाओं पर नियंत्रण के माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नतीजतन, यह क्षेत्र तेजी से विद्वानों द्वारा वर्णित महासागरों के राजनीतिकरण का प्रतीक बन रहा है, जहाँ समुद्र न केवल एक मार्ग के रूप में बल्कि प्रतिस्पर्धा, दबाव और प्रभाव दिखाने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है।

इस शक्ति पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम खोजा गया आयाम डिजिटल भू–राजनीति है, विशेष रूप से समुद्र के नीचे फाइबर–ऑप्टिक केबलों का रणनीतिक महत्व। ये केबल वैश्विक डेटा ट्रैफिक का 97 प्रतिशत से अधिक ले जाते हैं, जिसमें इंटरनेट संचार, वित्तीय लेनदेन और संवेदनशील सरकारी आदान–प्रदान शामिल हैं, जो उन्हें वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाते हैं। भारत की रणनीतिक भूगोल – 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा और मलक्का जलडमरूमध्य, बाब–अल–मंडेब और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स के निकटता इसे हिंद–प्रशांत में एक संभावित डिजिटल और समुद्री पारगमन केंद्र के रूप में स्थापित करती है। नतीजतन, डिजिटल बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और विस्तार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की गणना का एक अभिन्न अंग बन गया है। बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से डिजिटल सिल्क रोड जैसी पहलों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव, ने भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों को तकनीकी निर्भरता और आपूर्ति–श्रृंखला कमजोरियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल अब निगरानी, डेटा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ी चिंताओं से जुड़ गया है, जो भारत की इंडो–पैसिफिक रणनीति के मुख्य स्तंभ के रूप में डिजिटल संप्रभुता की खोज को मजबूत करता है। इस संदर्भ में, समान विचारधारा वाले भागीदारों – विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों – के साथ भारत का बढ़ता सहयोग चीन की तकनीकी और समुद्री आक्रामकता का मुकाबला करने के प्रयास को दर्शाता है, साथ ही एक लचीले, विविध डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करता है।

समुद्री भू–राजनीति भारत की भू–रणनीतिक वास्तुकला का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) दुनिया के कुछ सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों का घर है, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 75 प्रतिशत और समुद्री तेल व्यापार का लगभग 80 प्रतिशत गुजरता है। इसमें से, लगभग 40 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य से, 35 प्रतिशत मलक्का जलडमरूमध्य से और 8 प्रतिशत बाब–अल–मंडेब जलडमरूमध्य से गुजरता है। इन जलमार्गों को समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ने, हथियारों की तस्करी और पर्यावरणीय गिरावट सहित बढ़ते गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का संगम समुद्री क्षेत्र जागरूकता, क्षेत्रीय सूचना–साझाकरण तंत्र और सहकारी सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है – ऐसे क्षेत्र जहां भारत ने खुद को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है।

इंडो–पैसिफिक का रणनीतिक महत्व ताइवान जलडमरूमध्य संकट से और बढ़ गया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला और बड़ी शक्तियों के संबंधों के लिए दूरगामी प्रभावों वाले एक फ्लैशपॉइंट के रूप में उभरा है। जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव न केवल पूर्वी एशियाई सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, बल्कि व्यापक इंडो–पैसिफिक में भी गूंजते हैं, जिससे भारत का रणनीतिक माहौल प्रभावित होता है। एक संभावित संघर्ष महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री कनेक्टिविटी को बाधित कर सकता है,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

जिससे भारत को क्षेत्रीय और अतिरिक्त–क्षेत्रीय भागीदारों के साथ समन्वय में अपनी रणनीतिक स्थिति को फिर से समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

ये घटनाक्रम भारत–चीन के बीच चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में सामने आते हैं, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक शिकायतों और समकालीन शक्ति विषमताओं में हैं। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दौर में चीन–भारतीय सहयोग की एक आदर्शवादी दृष्टि देखी गई, जो वैचारिक एकजुटता और उत्तर–औपनिवेशिक आकांक्षाओं पर आधारित थी। हालांकि, यह भ्रम 1962 के भारत–चीन युद्ध के साथ टूट गया, जिससे द्विपक्षीय संबंध अविश्वास, अनसुलझे सीमा विवादों और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से चिह्नित हो गए। हालिया सीमा गतिरोध और हालिया सीमा विवाद और इंडो–पैसिफिक में चीन की बढ़ती मौजूदगी – बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क से लेकर नौसैनिक तैनाती तक – वैचारिक जुड़ाव से भू–राजनीतिक अतिक्रमण की ओर बदलाव का संकेत देते हैं, जो चीन को भारत के प्राथमिक रणनीतिक चौलेंजर के रूप में भारत की धारणा को मजबूत करता है।

इस पृष्ठभूमि में, यह अध्ययन जांच करता है कि इंडो–पैसिफिक में भारत की भू–रणनीतिक वास्तुकला को डिजिटल संप्रभुता, समुद्री भू–राजनीति, ताइवान जलडमरूमध्य संकट और चीन–भारत रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्संबंधों के माध्यम से कैसे पुनर्गठित किया जा रहा है। अकादमिक साहित्य, सरकारी रिपोर्ट, नीतिगत दस्तावेजों और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय डेटा सहित माध्यमिक स्रोतों पर आधारित एक गुणात्मक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, यह शोध भारत के रणनीतिक व्यवहार को आकार देने वाले संरचनात्मक चालकों को उजागर करने का प्रयास करता है। भारत की इंडो–पैसिफिक रणनीति को व्यापक क्षेत्रीय शक्ति संक्रमणों के भीतर स्थापित करके, यह अध्ययन बहुध्रुवीयता, रणनीतिक स्वायत्तता और डिजिटल–समुद्री युग में भू–राजनीति की विकसित प्रकृति पर समकालीन बहसों में योगदान देता है।

<u>ताइवान जलडमरूमध्य संकट और हिंद–प्रशांत में भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ</u>: आज की वैश्विक राजनीति तीव्र अस्थिरता और बढ़ते भू–राजनीतिक जोखिमों के दौर से गुजर रही है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचनात्मक नींव लगातार कमजोर होती जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित उदार वैश्विक व्यवस्था का क्षरण, विशेषतः एकतरफा शक्ति–प्रयोग, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और महान शक्ति राजनीति की वापसी के कारण, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की संभावना को अधिक यथार्थवादी बना रहा है। इसी संदर्भ में ताइवान जलडमरूमध्य हिंद–प्रशांत क्षेत्र का सबसे संवेदनशील और संभावित रूप से विस्फोटक भू–रणनीतिक केंद्र बनकर उभरा है। ताइवान जलडमरूमध्य केवल क्षेत्रीय विवाद का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह दो प्रतिस्पर्धी शक्ति संरचनाओं—संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले उदार, नियम–आधारित व्यवस्था और चीन की उभरती शक्ति–केन्द्रित, संप्रभुता–प्रधान दृष्टि—के बीच टकराव का प्रतीक है। 1950 के दशक में ही भारत के नेतृत्व ने इस जलडमरूमध्य को एक संभावित भू–रणनीतिक फ्लैशप्वाइंट के रूप में पहचाना था, और इक्कीसवीं सदी में यह आकलन और अधिक प्रासंगिक हो गया है।

2020 के दशक में चीन द्वारा ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि— (जिसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नियमित सैन्य अभ्यास, हवाई पहचान क्षेत्र में घुसपैठ, और समुद्री घेराबंदी के संकेत शामिल हैं)ने इस संकट को मात्र सैद्धांतिक नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीतिक चुनौती बना दिया है। अमेरिकी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

सैन्य नेतृत्व द्वारा यह चेतावनी कि चीन 2027 तक ताइवान पर बलपूर्वक कार्रवाई करने की क्षमता विकसित कर सकता है, इस संकट को रणनीतिक योजना के केंद्र में ले आती है। यद्यपि क्षमता और इरादे के बीच अंतर करना आवश्यक है, फिर भी चीन की अपारदर्शी राजनीतिक प्रणाली और शी जिनपिंग के दीर्घकालिक राष्ट्रवादी लक्ष्यों के कारण इस अनिश्चितता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी नीति की रणनीतिक अस्पष्टता (Strategic Ambiguity) इस संकट को और जटिल बनाती है। यद्यपि औपचारिक रूप से अमेरिका ने ताइवान रक्षा अधिनियम के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को अस्पष्ट रखा है, फिर भी हाल के वर्षों में अमेरिकी वक्तव्यों और सैन्य संकेतों ने चीन के लिए गलत आकलन (Miscalculation) की संभावना बढ़ा दी है। यही वह बिंदु है जहाँ एक सीमित क्षेत्रीय संकट व्यापक हिंद–प्रशांत संघर्ष में परिवर्तित हो सकता है।

Map: *Taiwan Strait*

The Formosa Strait, commonly known as the Taiwan Strait, is an approximately 180-kilometre-wide maritime passage separating the island of Taiwan from mainland Asia. It extends between the coast of China's Fujian Province and the western shores of Taiwan.

Source: https://www.iasgyan.in/daily— current— affairs/taiwan— strait— 44

भारत के लिए ताइवान जलडमरूमध्य संकट केवल दूरस्थ पूर्वी एशिया का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह उसकी आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति–श्रृंखला स्थिरता, समुद्री व्यापार, और रणनीतिक स्वायत्तता से सीधे जुड़ा हुआ है। वैश्विक अर्धचालक आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा ताइवान से आता है, और किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में वैश्विक उत्पादन, तकनीकी उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। भारत, जो स्वयं को एक प्रमुख विनिर्माण और तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, ऐसे व्यवधानों से अप्रभावित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त, ताइवान संकट का भारत–चीन संबंधों पर अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा प्रभाव पड़ेगा। चीन द्वारा ताइवान पर बल प्रयोग की स्थिति में, भारत–चीन सीमा विवाद, हिंद

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

महासागर में चीनी नौसैनिक गतिविधियाँ, और डिजिटल तथा आर्थिक दबाव के साधन अधिक तीव्र हो सकते हैं। यह भारत को एक बहु–आयामी रणनीतिक चुनौती के समक्ष खड़ा करेगा, जहाँ उसे एक साथ महाद्वीपीय, समुद्री और डिजिटल क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

Figure: Why Taiwan should matter to India

Source:

- Vijay Gokhale, "*[* Why Taiwan should matter to India*]*," *The New Indian Express*, May 19, 2025,
- **https://images.assettype.com/newindianexpress/2025— 04— 15/lau7uwer/The— New— Indian— Express— Logo.png**

इस संदर्भ में भारत–ताइवान सहयोग की संभावनाएँ केवल कूटनीतिक प्रतीकात्मकता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक व्यवहारिकता का प्रश्न हैं। अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत विनिर्माण, और आपूर्ति–श्रृंखला विविधीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत की आर्थिक लचीलापन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ कर सकता है। यह सहयोग **'वन–चाइना नीति'** के औपचारिक ढाँचे के भीतर रहते हुए भी व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि कई अन्य लोकतांत्रिक देशों ने किया है। अतः यह स्पष्ट है कि ताइवान जलडमरूमध्य में होने वाला कोई भी घटनाक्रम भारत के लिए परोक्ष नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रणनीतिक निहितार्थ रखता है। इसे नजरअंदाज करना भारत की उभरती भू–रणनीतिक भूमिका, हिंद–प्रशांत में उसकी विश्वसनीयता, और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के विपरीत होगा। भारत के नीति–निर्माताओं, रणनीतिक समुदाय और आर्थिक नेतृत्व को इस संकट को एक दूरस्थ क्षेत्रीय विवाद के रूप में नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति संरचना के एक निर्णायक परीक्षण के रूप में देखना

भारत–चीन सीमा विवाद और भू–राजनीतिक रणनीतियाँ:वैचारिक भ्रम से भू–राजनीतिक अतिक्रमण तक:

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थान–नामों को बदलना केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, बल्कि यह उसकी कार्टोग्राफिक आक्रामकता (Cartographic Aggression) का हिस्सा है। इसके माध्यम से चीन विवादित क्षेत्रों पर अपने संप्रभुता दावों को वैध ठहराने का प्रयास करता है। लद्दाख क्षेत्र में चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति इस नीति का व्यावहारिक रूप है, जिसके तहत छोटे–छोटे, क्रमिक और सीमित कदमों के माध्यम

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

से यथास्थिति को धीरे–धीरे अपने पक्ष में बदला जाता है। यह रणनीति प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए विरोधी की प्रतिक्रिया क्षमता को क्षीण करती है और दीर्घकाल में भू–भागीय नियंत्रण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को स्थलीय सीमा पर लगातार व्यस्त रखना है, ताकि वह अपनी नौसैनिक क्षमताओं और समुद्री आधुनिकीकरण पर पूर्ण ध्यान न दे सके। सीमित संसाधनों और रक्षा बजट की वास्तविकताओं के कारण, सीमा पर बढ़ता दबाव भारत की समुद्री शक्ति के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

उन्नीसवीं शताब्दी में अल्फ्रेड थायर महान द्वारा प्रतिपादित समुद्री शक्ति सिद्धांत (Sea Power Theory) के अनुसार, किसी भी राष्ट्र की वैश्विक शक्ति उसकी नौसैनिक क्षमता और समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण से निर्धारित होती है। चीन आज इसी सिद्धांत का आधुनिक रूप अपनाता हुआ दिखाई देता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), विशेष रूप से इसका मैरिटाइम सिल्क रोड घटक, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने का माध्यम है। ग्वादर (पाकिस्तान), हंबनटोटा (श्रीलंका), क्यौकफ्यू (म्यांमार) और जिबूती जैसे बंदरगाह चीन की तथाकथित String of Pearls रणनीति को आाकार प्रदान करते हैं।

साथ ही, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) का तीव्र आधुनिकीकरण चीन की वैश्विक समुद्री महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट करता है—ठीक उसी प्रकार, जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन ने एक सशक्त नौसेना के माध्यम से वैश्विक प्रभुत्व स्थापित किया था।

Map: *Line of Actual Control & POK*

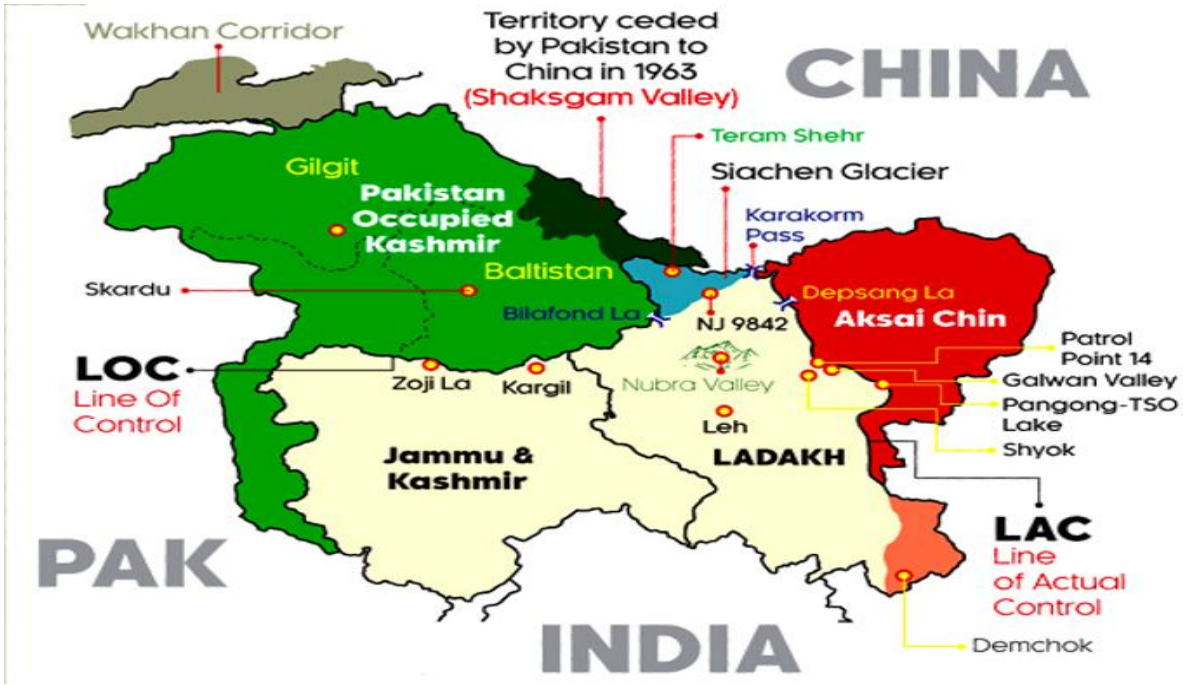

➢ Line of Actual Control (LAC) is the line separating Indian areas of Jammu and Kashmir from Aksai Chin. It is concurrent with the Chinese Aksai Chin claim line.

Source: https://www.ias4sure.com/wikiias/gs2/india— china— border— disputes/

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

रणनीतिक संतुलन और भारत की प्राथमिकताएँ : रणनीतिक विशेषज्ञों का व्यापक मत है कि भारत और चीन के बीच पूर्ण पैमाने का पारंपरिक युद्ध अपेक्षाकृत असंभाव्य है, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। तथापि, हिंद महासागर जैसे भू–रणनीतिक समुद्री क्षेत्र—जहाँ वैश्विक व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्ग और चोक–पॉइंट्स स्थित हैं—भविष्य में प्रतिस्पर्धा और तनाव का मुख्य केंद्र बन सकते हैं।

इस संदर्भ में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में निम्नलिखित तत्व निर्णायक हैं:

- क्षेत्रीय समुद्री प्रभुत्व को सुदृढ़ करना
- भारतीय नौसेना का तीव्र आधुनिकीकरण
- हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदार देशों के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार

भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह एक ओर सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करे, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति और समुद्री कूटनीति को व्यापक बनाए। क्वाड जैसे मंचों और बहुपक्षीय साझेदारियों के माध्यम से चीन के विस्तारवाद का संतुलन स्थापित करना भारत की दीर्घकालिक भू–राजनीतिक रणनीति का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

भारत–चीन सीमा विवाद केवल भू–भागीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह व्यापक भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, समुद्री शक्ति संतुलन और वैश्विक नेतृत्व की होड़ से गहराई से जुड़ा हुआ है। वैचारिक आदर्शवाद से निकलकर आज यह संघर्ष रणनीतिक यथार्थवाद के चरण में प्रवेश कर चुका है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह स्थलीय और समुद्री—दोनों आयामों को समन्वित करते हुए एक सुसंगत, दीर्घकालिक और बहुआयामी भू–रणनीतिक नीति विकसित करे, जिससे वह न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके, बल्कि इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में एक स्थिर और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर सके।

Source:

- Pavneet singh Youtube blog
- https://www.youtube.com/watch?v=vEnqhQ2_DdM&t=959s

डेटा सुरक्षा से भू–सुरक्षा तक: हिंद–प्रशांत में भारत की डिजिटल संप्रभुता रणनीति का आलोचनात्मक विश्लेषण:

हिंद–प्रशांत क्षेत्र इक्कीसवीं सदी में केवल समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक डिजिटल प्रवाह, डेटा संप्रभुता और तकनीकी प्रभुत्व का निर्णायक भू–रणनीतिक रंगमंच बन चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में सबमरीन फाइबर–ऑप्टिक केबल्स आधुनिक वैश्विक व्यवस्था की वह अदृश्य लेकिन निर्णायक अवसंरचना हैं, जिनके माध्यम से 95–97 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक, वित्तीय लेन–देन और सरकारी–सैन्य संचार संचालित होता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की यह रीढ़ अब केवल तकनीकी संसाधन न होकर रणनीतिक संपत्ति में रूपांतरित हो चुकी है, जिसके नियंत्रण, सुरक्षा और निर्भरता ने पारंपरिक भू–राजनीति को **"डिजिटल भू–सुरक्षा"** के नए चरण में प्रवेश करा दिया है।

भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति तथा मलक्का जलडमरूमध्य, होर्मुज और बाब–अल–मंडेब जैसे वैश्विक समुद्री चोक–पॉइंट्स के समीपता ने उसे स्वाभाविक रूप से एक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

संभावित डिजिटल ट्रांजिट हब बना दिया है। वर्तमान में भारत 17 अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल्स का लैंडिंग देश है, जिनमें से 15 मुंबई के सीमित भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित हैं। यह संरचनात्मक एकाग्रता, जहाँ भारत को वैश्विक कनेक्टिविटी से जोड़ती है, वहीं यह एक गंभीर रणनीतिक कमजोरी भी उत्पन्न करती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएँ, साइबर–हाइब्रिड हस्तक्षेप या जानबूझकर की गई तोड़फोड़ संपूर्ण डिजिटल पारिस्थितिकी को बाधित कर सकती है।

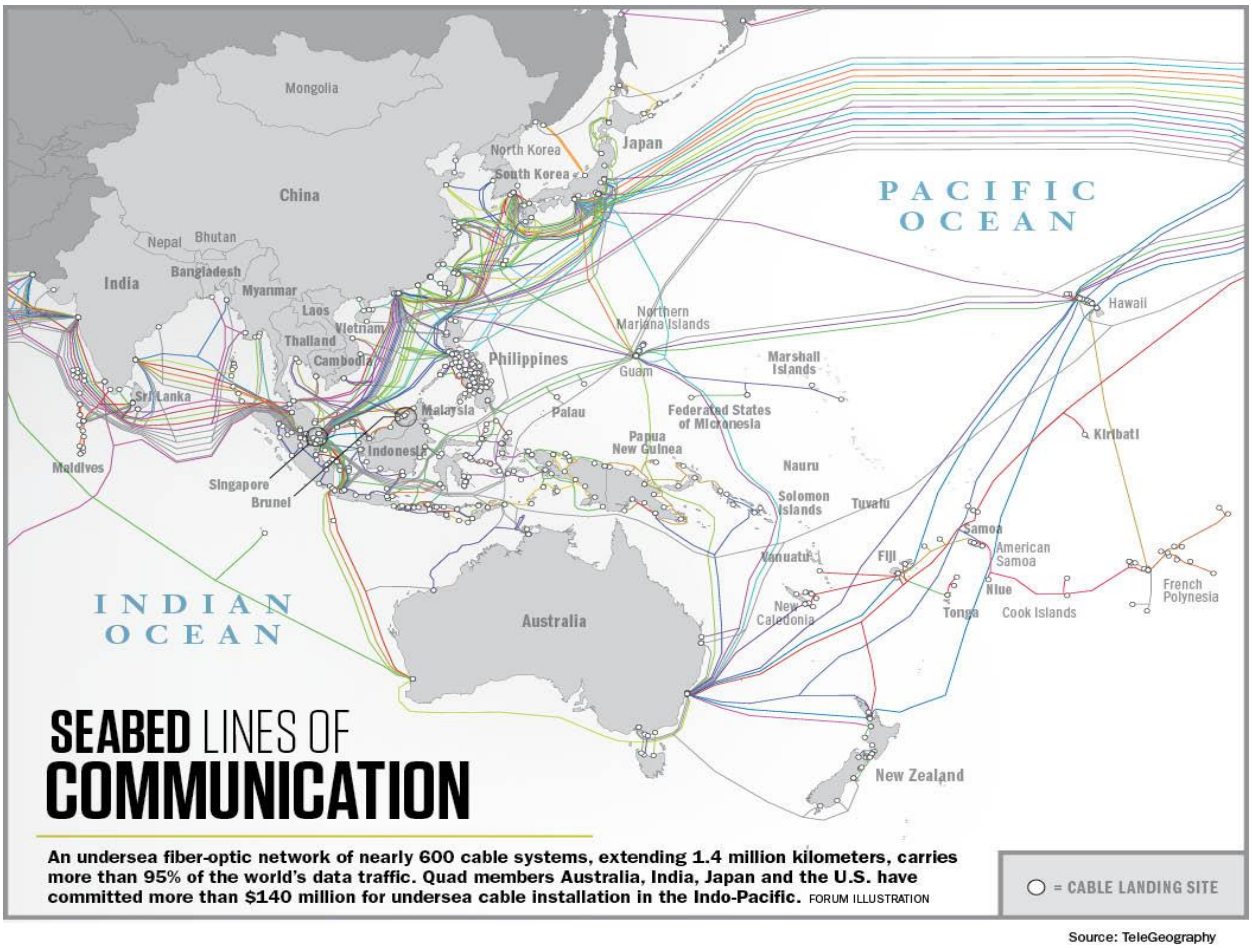

Map: *Lines of communication*
Sourse: **https://ipdefenseforum.com/2025/04/critical— conduits/**

हिंद–प्रशांत में बढ़ती भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने फाइबर–ऑप्टिक केबल्स को **"मौन रणनीतिक हथियार"** में परिवर्तित कर दिया है। चीन की डिजिटल सिल्क रोड, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का डिजिटल विस्तार है, ने इस क्षेत्र में केबल निर्माण, स्वामित्व और रखरखाव के माध्यम से प्रभाव का एक समानांतर नेटवर्क खड़ा किया है। 2021 से 2026 के बीच 20 से अधिक सबमरीन केबल परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की भागीदारी ने डेटा अवरोधन, जासूसी और रणनीतिक दबाव की आशंकाओं को गहरा किया है। ताइवान के मात्सु द्वीप के निकट 2024 में केबल कटने की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि सबमरीन केबल्स अब पारंपरिक सैन्य टकराव के बिना दबाव बनाने के साधन के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं, जो हाइब्रिड युद्ध की उभरती प्रवृत्ति को रेखांकित करता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

भारत के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती प्रस्तुत करती है—एक ओर चीनी–नियंत्रित डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता को कम करना, और दूसरी ओर स्वयं को एक सुरक्षित, भरोसेमंद और नियम–आधारित डिजिटल शक्ति के रूप में स्थापित करना। भारत की समुद्री दृष्टि, SAGAR (Security and Growth for All in the Region) और Indo–Pacific Oceans Initiative (IPOI), डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा को समुद्री सुरक्षा के व्यापक विमर्श में एकीकृत करती हैं। क्वाड ढाँचे के अंतर्गत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा पारदर्शी, सुरक्षित और टिकाऊ कनेक्टिविटी पर दिया जा रहा बल, चीन के तकनीकी प्रभुत्व के विकल्प के रूप में उभर रहा है।

सबमरीन केबल्स की असुरक्षा केवल राज्य–प्रायोजित हस्तक्षेप तक सीमित नहीं है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र का **"रिंग ऑफ फायर"** भूकंप, समुद्री भूस्खलन और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अत्यंत संवेदनशील है। 2006 के ताइवान भूकंप और 2022 के टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एकल केबल विफलता कैसे पूरे राष्ट्र को डिजिटल रूप से अलग–थलग कर सकती है। भारत में केबल लैंडिंग की अत्यधिक एकाग्रता इस जोखिम को और बढ़ा देती है, विशेषकर तब जब केबल मरम्मत के लिए देश अब भी सिंगापुर और दुबई स्थित विदेशी जहाजों पर निर्भर है, जिनकी प्रतिक्रिया अवधि तीन से पाँच महीने तक हो सकती है।

इस संदर्भ में भारत की डिजिटल संप्रभुता रणनीति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता, वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखला और वित्तीय प्रणाली की निरंतरता से भी जुड़ जाती है। प्रतिदिन लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक वित्तीय लेन–देन सबमरीन केबल्स पर निर्भर हैं। किसी भी बड़े व्यवधान का प्रभाव भारत की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा–सेंटर पारिस्थितिकी और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति–श्रृंखला पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत को मुंबई–केंद्रित संरचना से आगे बढ़ते हुए विशाखापत्तनम, पारादीप, कांडला और कोच्चि जैसे वैकल्पिक डिजिटल हब विकसित करने की आवश्यकता है।

तकनीकी नवाचार इस रणनीति का अनिवार्य घटक है। रीयल–टाइम केबल मॉनिटरिंग, एन्क्रिप्शन–आधारित डेटा सुरक्षा, रणनीतिक अतिरेक (Redundancy) और घरेलू केबल–मरम्मत बेड़े का विकास भारत की डिजिटल लचीलापन को सुदृढ़ कर सकता है। भारत–अमेरिका के बीच TRUST (Technology for Resilient, Open and Unified Security and Trust) ढाँचा और 2025 के संयुक्त वक्तव्य में घोषित मेटा की 50,000 किलोमीटर लंबी केबल परियोजना, इस सहयोगी डिजिटल भू–रणनीति के ठोस संकेतक हैं।

हालाँकि, तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेष रूप से UNCLOS, सबमरीन केबल सुरक्षा के संदर्भ में सीमित प्रवर्तन क्षमता रखता है। तोड़फोड़, जासूसी और हाइब्रिड हस्तक्षेप जैसे समकालीन खतरों के लिए बहुपक्षीय कानूनी ढाँचे का अद्यतन आवश्यक है। भारत, क्वाड और आसियान मंचों के माध्यम से साझा निगरानी, संयुक्त प्रतिक्रिया और जवाबदेही आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है। साथ ही, भारत की घरेलू लाइसेंसिंग प्रक्रिया—जिसमें 50 से अधिक स्वीकृतियाँ शामिल हैं—डिजिटल अवसंरचना विस्तार में एक प्रमुख बाधा बनी हुई है, जिसे सुव्यवस्थित करना अनिवार्य है।

इस प्रकार, हिंद–प्रशांत में सबमरीन फाइबर–ऑप्टिक केबल्स भारत के लिए केवल तकनीकी अवसंरचना नहीं, बल्कि भू–रणनीतिक शक्ति, आर्थिक स्थिरता और डिजिटल संप्रभुता का आधार हैं। डेटा सुरक्षा से भू–सुरक्षा तक की यह यात्रा भारत को एक निष्क्रिय उपभोक्ता से सक्रिय नियम–निर्माता की भूमिका में ले

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

जाती है। क्षेत्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और कानूनी सुदृढ़ता के समन्वय से भारत न केवल चीनी डिजिटल प्रभुत्व को संतुलित कर सकता है, बल्कि वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक भलाई के संरक्षण में भी नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका: विस्तारवाद, सुरक्षा और भू–राजनीतिक प्रभाव: हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के बाद चीन एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है जो आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली है। चीन की साम्यवादी शासन प्रणाली और उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के कारण यह क्षेत्र लगातार भू–राजनीतिक तनावों का केंद्र बनता जा रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, आसियान देशों और भारत सहित कई प्रमुख राष्ट्र उसकी रणनीतिक गतिविधियों पर गंभीर दृष्टि बनाए हुए हैं।

चीन ने हाल के वर्षों में हिंद–प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने आर्थिक, व्यापारिक और नौसैनिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इस क्रम में चीन ने अपनी आर्थिक और सामरिक रणनीति को और अधिक संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से बीजिंग में 'एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' ***(AIIB)*** की स्थापना की। यह बैंक मुख्यतः एशिया में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से यह चीन की वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। यह संस्थान पश्चिम–प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ***(IMF)*** और जापान–समर्थित एशियाई विकास बैंक ***(ADB)*** के समकक्ष खड़ा किया गया, जिससे चीन न केवल वैश्विक आर्थिक नेतृत्व में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके, बल्कि 'ब्रेटन वुड्स संस्थानों' के एकाधिकार को चुनौती भी दे सके।

चीन अपनी आर्थिक प्रभावशीलता को ***"बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव"*** (***BRI***) और **"चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा"** (***CPEC***) जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बढ़ा रहा है। ***CPEC*** पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, जिससे चीन मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर पर अपनी निर्भरता को कम कर, अरब सागर के माध्यम से ऊर्जा और व्यापार आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। यह रणनीति चीन को किसी भी आपात स्थिति में वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है।

BRI के अंतर्गत चीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सड़कों, जलमार्गों, तेल पाइपलाइनों, बंदरगाहों, ऊर्जा ग्रिड और अन्य बुनियादी ढांचे से जोड़ने का कार्य कर रहा है। यह परियोजना लगभग 68 देशों को जोड़ती है, जो वैश्विक जनसंख्या का 60: और वैश्विक व्यापार का लगभग 40: हिस्सा हैं, और यह एक बहु–ट्रिलियन डॉलर की योजना मानी जाती है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में 18 गहरे पानी के बंदरगाहों (***Deep water ports***) का निर्माण कर रहा है, जिनमें से अधिकांश विकासशील देशों में हैं, जो आर्थिक निवेश और बुनियादी ढांचे के लिए चीन पर निर्भर हैं।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा ***"String of Pearls"*** अर्थात् ***'मोतियों की माला'*** जैसी रणनीतिक अवधारणा का पहला उल्लेख वर्ष 2005 में अमेरिकी रक्षा विश्लेषण संस्था ***Booz Allen Hamilton*** द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में हुआ था। इस रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में एक भू–राजनीतिक माला का निर्माण कर रहा है, जिसमें वह रणनीतिक ठिकानों, बंदरगाहों और समुद्री अवसंरचना के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। यह संकल्पना वास्तव में अमेरिकी सामरिक चिंताओं का प्रतिबिंब थी।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

Map: Chinies One Road, One Belt

Source:

➢ https://www.sirjournal.org/research/2019/7/1/indias— maritime— wall— in— the— indo— pacific— region

इस अवधारणा के तहत चीन की रणनीति केवल आर्थिक हितों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व को संतुलित करने के लिए भी कार्यरत है। इसके अंतर्गत वह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपने 'मोती' अर्थात रणनीतिक ठिकानों को विकसित कर रहा है। इन मोतियों में ग्वादर (पाकिस्तान), हम्बनटोटा (श्रीलंका), क्यौकफ्यू (म्यांमार), चिट्टगोंग (बांग्लादेश) और जिबूती जैसे स्थान शामिल हैं, जहां चीन ने सैन्य और वाणिज्यिक निवेश के माध्यम से स्थायी उपस्थिति दर्ज कराई है।

इस रणनीतिक विस्तार का एक प्रमुख उद्देश्य मलक्का दुविधा (***Malacca Dilemma***) से बाहर निकलना है, जहाँ चीन अपनी ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों को अमेरिका या अन्य पश्चिमी शक्तियों के संभावित दबाव से मुक्त करना चाहता है। इस प्रक्रिया में चीन हिंद महासागर में एक दीर्घकालिक, बहुआयामी उपस्थिति स्थापित कर रहा है, जो पारंपरिक सैन्य रणनीति के साथ–साथ बंदरगाह प्रौद्योगिकी, समुद्री व्यापार, ऋण–राजनीति (***Debt Diplomacy***) और सॉफ्ट पावर जैसे तत्वों को भी समाहित करती है।

भारत के दृष्टिकोण से यह रणनीति एक प्रकार के सामरिक घेराव (***Strategic Encirclement***) के रूप में देखी जाती है। परिणामस्वरूप, भारत की विदेश नीति में स्पष्ट बदलाव आया है, जिसमें ***"Act East Policy", SAGAR (Security and Growth for All in the Region) Doctrine*** और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में गठबंधनों की ओर झुकाव देखा गया है।

अतः ***"String of Pearls"*** कोई स्थिर या सीमित रणनीति नहीं है, बल्कि यह चीन की गतिशील, बहुआयामी और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का प्रतीक है। यह अवधारणा अब 21वीं सदी की समुद्री भू–राजनीतिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

प्रतिस्पर्धा का एक केंद्रीय विषय बन चुकी है, जिसकी निरंतर निगरानी, विश्लेषण और संतुलन की आवश्यकता है — विशेषकर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए, जो हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति–संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चीन ***'हिंद–प्रशांत'*** शब्दावली के स्थान पर '***एशिया–प्रशांत***' शब्द का प्रयोग करता है, जिससे उसकी भू–राजनीतिक अवधारणाओं की पुष्टि होती है। महाशक्ति बनने की राह में चीन के लिए एशिया, अफ्रीका और हिंद–प्रशांत क्षेत्र के तटीय देश अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रणनीतिक दृष्टिकोण से ***BRM 'Base'*** (सैन्य ठिकाने), ***'Reserve'*** (संसाधन भंडार), और '***Market***' (वाणिज्यिक बाजार)—इन तीनों आयामों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए चीन मैरिटाइम सिल्क रोड, चाइना–पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (***CPEC***), वन बेल्ट वन रोड (***OBOR***) और 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' जैसी बहुस्तरीय परियोजनाओं पर सक्रियता से कार्य कर रहा है। 9 दिसंबर 2017 को श्रीलंका ने "***हंबनटोटा बंदरगाह***" को औपचारिक रूप से चीन को 99 वर्षों के लिए लीज पर सौंप दिया, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (***BRI***) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस निर्णय ने वैश्विक भू–राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई प्रश्न उठाए, और कई विशेषज्ञ इसे ***"डेट ट्रैप डिप्लोमेसी"*** (***Debt Trap Diplomacy***) का उदाहरण मानते हैं। इस अवधारणा के अनुसार, चीन ने विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर ऋण प्रदान किया, जो अंततः उन देशों के आर्थिक संकट को बढ़ा दिया, और बदले में चीन को रणनीतिक ठिकानों और संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ।

बांग्लादेश के संदर्भ में भी चीन की रणनीतिक सक्रियता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। चीन ने चिटगांव बंदरगाह में निवेश किया है, बल्कि इसके साथ–साथ एक परमाणु रिएक्टर प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा, जो उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2002 में दोनों देशों के बीच एक रक्षा सहयोग समझौता भी संपन्न हुआ, जिससे बांग्लादेश के सैन्य आधुनिकीकरण में चीन की भागीदारी बढ़ी। इसी प्रकार, मालदीव, जो भारत के तट से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां भी चीन ने अपने रणनीतिक कदम तेज किए हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के अनुसार, चीन ने अब तक 17 द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जो उसकी समुद्री विस्तारवादी नीति की ओर संकेत करता है। मालदीव अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (***BRI***) का हिस्सा बन चुका है, जिससे उसकी भू–राजनीतिक स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। इन दोनों देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति केवल आर्थिक निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य, तकनीकी और बुनियादी ढांचे के आयाम भी शामिल हैं, जो हिंद महासागर में भारत की सामरिक स्थिति के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहे हैं।

वर्तमान में चीन अमेरिका और रूस के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना शक्ति के रूप में उभर चुका है, और वह इस स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु नौसेना के आधुनिकीकरण और विस्तार में भारी निवेश कर रहा है। इसका उद्देश्य न केवल हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को सुनिश्चित करना है, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर भी प्रभाव स्थापित करना है।

दक्षिण चीन सागर में चीन के कथित ***"नाइन डैश लाइन"*** दावे और कृत्रिम द्वीप निर्माण जैसी गतिविधियों ने इस क्षेत्र को अत्यंत विवादास्पद बना दिया है। इन द्वीपों पर चीन ने हवाई पट्टियों, एंटी–एयरक्राफ्ट गनों,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नौसैनिक अड्डों जैसी सैन्य संरचनाओं का विकास किया है। इन गतिविधियों की पुष्टि समय–समय पर पेंटागन द्वारा जारी उपग्रह चित्रों से होती रही है। वर्ष 2009 तक दक्षिण चीन सागर एक अपेक्षाकृत शांत जलक्षेत्र था, जहां क्षेत्रीय विवाद नगण्य थे। किंतु बीते 16 वर्षों में यह क्षेत्र चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति और तथाकथित ***"नाइन डैश लाइन"*** दावे के कारण एक अत्यंत विवादित क्षेत्र बन चुका है। चीन के इस एकतरफा समुद्री दावे के विरुद्ध वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस जैसे पांच प्रमुख तटीय देशों ने विरोध दर्ज किया है। स्प्रैटली द्वीप समूह को लेकर भी इन देशों के बीच गंभीर विवाद विद्यमान हैं। वर्ष 2016 में फिलीपींस के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (***Permanent Court of Arbitration***) द्वारा दिए गए निर्णय को भी चीन ने सिरे से खारिज कर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्री संप्रभुता की अवधारणाओं को चुनौती मिली।

क्रम संख्या **Sr. No.**	चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र **Areas under Chinese control in the Indo—Pacific Ocean**	स्थान **Locations**	प्रमुख विशेषताएँ **Main features**
1.	दक्षिण चीन सागर क्षेत्र (South China Sea Region)	पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्व एशिया के निकट	स्प्रैटली द्वीप समूह (Spratly Islands) और पार्सल द्वीप समूह (Paracel Island) पर क्षेत्रीय दावा, नौसैनिक ठिकाने और कृत्रिम द्वीप
2.	स्प्रैटली द्वीप समूह (Spratly Islands)	दक्षिण चीन सागर	कृत्रिम द्वीप और नौसैनिक अड्डे का निर्माण, क्षेत्रीय विवाद और सामरिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र
3.	पार्सल द्वीप समूह (Paracel Island)	दक्षिण चीन सागर	नौसैनिक और वायुसेना के अड्डे, क्षेत्रीय विवाद
4.	हम्बनटोटा बंदरगाह (Hambantota Port, श्रीलंका)	श्रीलंका, भारतीय महासागर	श्रीलंका सरकार से लीज पर, सामरिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण व्यापारिक और नौसैनिक केंद्र
5.	ग्वादर बंदरगाह (Gwadar Port, पाकिस्तान)	पाकिस्तान, अरब सागर, भारतीय महासागर	चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का हिस्सा, ऊर्जा और व्यापार मार्ग के लिए महत्त्वपूर्ण केंद्र
6.	कीरीबाती (Kiribati)	मध्य प्रशांत महासागर	चीन के साथ राजनयिक संबंध, नौसैनिक ठिकाने की योजना और सामरिक सहयोग
7.	जिबूती नौसैनिक अड्डा (Djibouti Naval Base)	जिबूती, अफ्रीका के Horn of Africa, पश्चिमी भारतीय महासागर	अफ्रीका में चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा, नौसैनिक और सैन्य उपस्थिति के लिए महत्त्वपूर्ण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

8.	मालदीव (Maldives)	मध्य भारतीय महासागर	आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास में प्रभाव, सामरिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग
9.	काम्बोडिया (Cambodia)	दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड की खाड़ी के पास	नौसैनिक ठिकाने और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग
10.	मेकॉन्ग नदी क्षेत्र (Mekong River Region)	दक्षिण पूर्व एशिया	जल संसाधनों और व्यापार मार्गों पर प्रभाव, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग
11	कोलंबो परियोजनाएं Colombo Projects	श्रीलंका, हिन्द महासागर	रियल एस्टेट परियोजनाएं, चीन की वित्तीय साझेदारी
12	क्रा नहर प्रस्ताव Kra Canal Proposal	थाईलैंड, अंडमान सागर	मलक्का जलडमरूमध्य का विकल्प, सामरिक महत्त्व
13	क्योकप्यू बंदरगाह Kyaukpyu Port	म्यांमार, राखाइन क्षेत्र	चीन–म्यांमार आर्थिक गलियारे का हिस्सा
14	सोलोमन द्वीप समूह Solomon Islands	मध्य प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया के पास	रक्षा सहयोग, संभावित सुरक्षा संधियाँ
15	वनुआतु द्वीप समूह Vanuatu Islands	दक्षिण–पश्चिम प्रशांत महासागर	चीन की बढ़ती सैन्य और राजनयिक उपस्थिति

पिछले दो वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में लगभग 3,200 एकड़ (लगभग 1,295 हेक्टेयर) क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर वहाँ सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। यह द्वीप हवाई पट्टियों, एंटी–एयरक्राफ्ट हथियारों, मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नौसैनिक ठिकानों से लैस हैं। चीन इस क्षेत्र में 200 समुद्री मील के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (***Exclusive Economic Zone***) का भी दावा करता है, जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (***UNCLOS***) की भावना के प्रतिकूल है।

दक्षिण चीन सागर में चीन की उपस्थिति केवल समुद्री प्रभुत्व की आकांक्षा नहीं दर्शाती, बल्कि यह उसकी भू–राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की स्पष्ट झलक भी है। चीन की यह नीति न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती है, बल्कि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि चीन एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति है, इसका यह अर्थ नहीं कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना कर मनमानी कर सकता है। भारत लगातार दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा का समर्थन करता रहा है।

हिन्द–प्रशांत महासागर में चीन के नियंत्रण या प्रभाव वाले क्षेत्रों की सूची

Chinese— Controlled or Influenced Areas in the Indo— Pacific Ocean:

पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन को अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाता है। अमेरिका गुआम के एंडरसन एयरबेस जैसे रणनीतिक ठिकानों से चीन पर राजनीतिक और नौसैनिक दबाव बनाए रखने की रणनीति अपनाए हुए है। अंतरराष्ट्रीय निवेश के क्षेत्र में भी चीन ने वैश्विक उपस्थिति दर्ज की है। वर्ष 2015 में चीन की एक कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन डीप–वॉटर पोर्ट का अधिग्रहण 38कृ 8 करोड़ डॉलर में किया, जो अमेरिकी मरीन का प्रमुख ठिकाना है, और इसे 99 वर्षों की लीज पर प्राप्त किया। इसी प्रकार, भूमध्य सागर स्थित ग्रीस के पीरियस पोर्ट को भी चीन ने अधिग्रहित कर लिया है, जिसे

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

वह यूरोप में प्रवेश के ***'ड्रैगन हेड'*** के रूप में विकसित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कई विकासशील देश, जो चीनी कर्ज में फंसे हुए हैं, जिबूती की तरह अपने प्रमुख बंदरगाहों को चीन को लीज पर देने को विवश हो सकते हैं। ईरान के साथ चीन के गहरे समुद्री और कूटनीतिक संबंध हैं, विशेष रूप से उस समय जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ भी चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त किया है।

साल 2018 में चीन ने एंटी–पायरेसी अभियानों के तहत सक्रिय नौसैनिक अभियान प्रारंभ किया, जो इस बात का संकेत था कि बीजिंग समुद्री सुरक्षा को लेकर पहले से अधिक सचेत और रणनीतिक हो चुका है। पश्चिम एशिया से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और अफ्रीकी देशों से विविध संसाधनों की आपूर्ति के कारण चीन की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा हिंद–प्रशांत क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हो चुकी है। चीन भलीभांति जानता है कि अमेरिकी प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार उसकी आर्थिक शक्ति और नौसैनिक प्रभुत्व है। अतः वह भी एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए अपने नौसैनिक और रणनीतिक विस्तार को सर्वोपरि मानता है। पूर्वी अफ्रीका के देशों—सूडान, जिंबाब्वे, मोजाम्बिक आदि में—चीन ने बुनियादी ढांचागत निर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही, हथियार, युद्धपोत तथा एंटी–शिप मिसाइलें भी चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड को आपूर्ति की हैं। चीन के हथियार और गोला–बारूद की बिक्री तंजानिया, इथियोपिया, सूडान, मिस्र, यमन और ईरान जैसे देशों में भी देखी जा रही है। अफ्रीकी महाद्वीप से भारी मात्रा में कच्चे माल का आयात चीन के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बन चुका है, जिससे यह क्षेत्र बीजिंग की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। हिंद महासागर में चीन ने जिबूती (लाल सागर) में अपना पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है, जो उसके वैश्विक रणनीतिक विस्तार का प्रतीक है।

हिन्द–प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के प्रमुख नौसैनिक अभ्यास

क्रम संख्या (Sr. No.)	Exercise Name	भागीदार देश (Participating Nation)	उद्देश्य / फोकस (Objective / Focus)
1.	Blue Sword (नीली तलवार)	चीन – पाकिस्तान	रणनीतिक नौसैनिक सहयोग और प्रशिक्षण
2.	Sea Guardians (समुद्री संरक्षक)	चीन – पाकिस्तान	आतंकवाद विरोधी समुद्री अभियान
3.	Peace Mission – SCO (शांति मिशन – एससीओ)	चीन, रूस, भारत, *SCO* देश	आतंकवाद–रोधी अभ्यास, सामूहिक सुरक्षा
4.	Joint Sea (संयुक्त सागर)	चीन – रूस	समुद्री युद्ध रणनीति और तालमेल
5.	Marine Security Belt (समुद्री सुरक्षा पट्टी)	चीन, रूस, ईरान	हिंद महासागर और फारस की खाड़ी में सहयोग
6.	Blue Strike (नीला प्रहार)	चीन – थाईलैंड	उभयचर युद्ध प्रशिक्षण
7.	ADMM–Plus Maritime Exercise	चीन, ***ASEAN***, भारत, अमेरिका आदि	आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

8.	PLAN Anti–Piracy Escort Mission	केवल चीन	अदन की खाड़ी में व्यापार मार्ग सुरक्षा
9.	South China Sea Combat Drills	केवल चीन	विवादित द्वीपों पर प्रभुत्व स्थापित करना
10.	China–Myanmar Naval Engagement	चीन – म्यांमार	बंदरगाह यात्राएं, प्रशिक्षण सहयोग
11.	China–Bangladesh Naval Exchange	चीन – बांग्लादेश	सैन्य सहयोग, युद्धपोत आपूर्ति
12.	China–Sri Lanka Port Calls	चीन – श्रीलंका	रणनीतिक आधारों पर पहुंच
13.	China–Indonesia Naval Drill	चीन – इंडोनेशिया	मानवीय सहायता, नौवहन सुरक्षा
14.	China–Cambodia Naval Exercise	चीन – कंबोडिया	सैन्य जुड़ाव और समुद्री अभ्यास
15.	China–Maldives Port Visit	चीन – मालदीव	हिन्द महासागर में रणनीतिक उपस्थिति
16.	China–Brunei Maritime Dialogue	चीन – ब्रुनेई	कूटनीतिक नौसैनिक संपर्क
17.	China–Timor&Leste Naval Diplomacy	चीन – तिमोर–लेस्ते	पूर्वी इंडोनेशिया में प्रभाव विस्तार
18.	China–Laos Riverine Drill	चीन – लाओस	मेकोंग नदी क्षेत्रीय सुरक्षा
19.	China–Vietnam Maritime Talks – Patrols	चीन – वियतनाम	सीमावर्ती समुद्री विवाद प्रबंधन
20.	Western Pacific Naval Symposium (WPNS)	बहुपक्षीय (Including— चीन)	नियम–आधारित नौवहन और विश्वास निर्माण

China's major naval exercise in the Indo— Pacific Ocean region

Source:

- U.S. Department of Defense's annual report: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China (2024)

- https://media.defense.gov/2024/Dec/18/2003615520/— 1/— 1/0/MILITARY— AND— SECURITY— DEVELOPMENTS— INVOLVING— THE— PEOPLES— REPUBLIC— OF— CHINA— 2024.PDF

भविष्य में किसी संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिका के द्वारा हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी से चीन की मुख्य भूमि को निशाना बनाए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, बीजिंग ने म्यांमार,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ गहरे रणनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। म्यांमार के क्याउकप्यू बंदरगाह और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के अलावा, चीन ने बांग्लादेश के चिटगांव में भी रणनीतिक निवेश किया है। सके अतिरिक्त, म्यांमार के इरावदी क्षेत्र को चीन ने 800 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के माध्यम से अपनी मुख्य भूमि से जोड़ने का कार्य किया है और ग्रेट कोको द्वीप पर रडार स्टेशन, हवाई पट्टी तथा लिसनिंग पोस्ट की स्थापना की जा रही है। इन सभी आयामों से स्पष्ट है कि चीन का वैश्विक भू–राजनीतिक दृष्टिकोण बहुस्तरीय है, जो न केवल आर्थिक निवेश और संसाधन अधिग्रहण पर केंद्रित है, बल्कि नौसैनिक व सैन्य प्रभुत्व को भी समान रूप से महत्व देता है। चीन द्वारा दक्षिण एशिया और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में किए जा रहे रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य विस्तार ने भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह खतरा केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समुद्री, साइबर, आर्थिक, कूटनीतिक और भू–राजनीतिक आयामों तक फैला हुआ है।

''निष्कर्ष''

यह अध्ययन प्रतिपादित करता है कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संरचनात्मक पुनर्गठन हो रहा है, जहाँ समुद्री भू–राजनीति, डिजिटल संप्रभुता और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अब पृथक क्षेत्र नहीं रह गए हैं, बल्कि परस्पर संबद्ध और एक–दूसरे को सुदृढ़ करने वाले शक्ति–क्षेत्र बन चुके हैं। इस संदर्भ में ताइवान जलडमरूमध्य केवल एक क्षेत्रीय तनाव–बिंदु नहीं, बल्कि नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखलाओं और एशिया में उभरती समुद्री–महाद्वीपीय रणनीतियों के संतुलन की सहनशीलता की परीक्षा है। भारत के लिए ताइवान जलडमरूमध्य से जुड़े घटनाक्रम किसी दूरस्थ परिदृश्य तक सीमित नहीं हैं; वे उसकी आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी स्वायत्तता, समुद्री स्थिरता और चीन के संदर्भ में उसकी रणनीतिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हिंद–प्रशांत में भारत की उभरती भू–रणनीतिक वास्तुकला समुद्री और डिजिटल आयामों के बढ़ते अभिसरण से आकार ले रही है। पनडुब्बी केबल, डेटा प्रवाह और डिजिटल अवसंरचना अब समुद्री संचार मार्गों (Sea Lines of Communication) का ही विस्तार बन चुके हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा का पुनर्परिभाषण हो रहा है। इस दृष्टि से भारत की डिजिटल संप्रभुता की खोज को तकनीकी राष्ट्रवाद की रक्षात्मक नीति नहीं, बल्कि समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में 'परस्पर–निर्भरता के हथियारीकरण' के प्रति एक अनुकूलनशील प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। SAGAR, **Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI)** और **Quadrilateral Security Dialogue (Quad)** जैसे ढाँचों में डिजिटल अवसंरचना सुरक्षा का समावेशन यह दर्शाता है कि भारत सुरक्षा को अब केवल सैन्य नहीं, बल्कि एक बहु–स्तरीय और हाइब्रिड अवधारणा के रूप में परिभाषित कर रहा है।

ताइवान जलडमरूमध्य संकट भारत–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की संरचनात्मक प्रकृति को भी तीक्ष्ण करता है। चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, डिजिटल सिल्क रोड के माध्यम से तकनीकी प्रभाव और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दबावकारी व्यवहार एक व्यापक रणनीति को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पदानुक्रम को पुनर्गठित करना और पड़ोसी देशों की रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करना है। इसके प्रत्युत्तर में भारत की समुद्री संतुलनकारी नीति, चयनात्मक आर्थिक विमुखता, तकनीकी विविधीकरण और सुदृढ़ साझेदारियाँ आदर्शवादी संलग्नता से यथार्थवादी समायोजन की ओर संक्रमण को दर्शाती हैं। महत्त्वपूर्ण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

रूप से, यह परिवर्तन रणनीतिक स्वायत्तता के परित्याग का संकेत नहीं है, बल्कि तीव्र महाशक्ति प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों में उसके पुनर्संयोजन को दर्शाता है।

यह अध्ययन आलोचनात्मक रूप से यह भी रेखांकित करता है कि भारत की रणनीति तब सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होती है जब वह द्विपक्षीय या गुटीय ध्रुवीकरण से बचते हुए मुद्दा–आधारित सहयोग, संस्थागत बहुलता और मानक–निर्माण (Norm–Setting) की भूमिका को अपनाता है। समुद्री सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के साथ सहयोग ने भारत की बाह्य संतुलन क्षमता को बढ़ाया है, जबकि रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण, डेटा स्थानीयकरण और आपूर्ति–श्रृंखला विविधीकरण जैसी घरेलू पहलें आंतरिक संतुलन को सुदृढ़ करती हैं। तथापि, पनडुब्बी केबल लैंडिंग की अत्यधिक एकाग्रता, विनियामक जटिलताएँ और अंडर–सी डोमेन अवेयरनेस में क्षमतागत सीमाएँ यह संकेत देती हैं कि दीर्घकालिक निवेश और शासन सुधार अनिवार्य हैं।

सैद्धांतिक स्तर पर, यह अध्ययन समकालीन भू–राजनीतिक विमर्श में योगदान देता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हिंद–प्रशांत में शक्ति का प्रयोग अब केवल भू–क्षेत्रीय नियंत्रण के माध्यम से नहीं, बल्कि डेटा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे प्रवाहों पर नियंत्रण के जरिए हो रहा है। भारत की उभरती रणनीति "रणनीतिक लचीलापन" (Strategic resilience) का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है, जो प्रतिरोध और सहयोग, प्रतिस्पर्धा और चयनात्मक संलग्नता के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह दृष्टिकोण शून्य–योग प्रतिस्पर्धा के विकल्प के रूप में उभरता है, विशेषकर ऐसे क्षेत्र में जहाँ किसी भी प्रकार का उभार या संघर्ष वैश्विक स्तर पर गहरे प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

अंततः, ताइवान जलडमरूमध्य संकट को भारत की हिंद–प्रशांत रणनीति में किसी एकल ट्रिगर के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्प्रेरक के रूप में समझा जाना चाहिए। यह भारत के लिए एक स्थिरता–प्रदाता, नियम–समर्थक और तकनीकी रूप से सक्षम शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित करता है। यदि भारत समुद्री शक्ति, डिजिटल संप्रभुता और बहुपक्षीय कूटनीति को एक सुसंगत दीर्घकालिक रणनीति में एकीकृत करने में सफल होता है, तो वह न केवल चीन के साथ अपनी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रभावी प्रबंधन कर सकेगा, बल्कि एक अधिक स्थिर, समावेशी और लचीली हिंद–प्रशांत व्यवस्था के निर्माण में भी सकारात्मक योगदान दे सकेगा।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका केवल आर्थिक साझेदारी या अवसंरचना विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित, बहुस्तरीय और दीर्घकालिक भू–रणनीतिक परियोजना का हिस्सा है। चीन का उभार इस क्षेत्र में एक ऐसे विस्तारवादी शक्ति–रूप में हुआ है, जो आर्थिक निवेश, कर्ज कूटनीति, समुद्री अवसंरचना, डिजिटल संपर्कता और सैन्य आधुनिकीकरण को एकीकृत कर क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन को अपने पक्ष में पुनर्संरचित करने का प्रयास कर रहा है।

Asian Infrastructure Investment Bank, Belt and Road Initiative तथा China–Pakistan Economic Corridor और 'मैरिटाइम सिल्क रोड' जैसी पहलों के माध्यम से चीन ने पश्चिम–प्रभावित वैश्विक वित्तीय और रणनीतिक संस्थानों के विकल्प प्रस्तुत किए हैं, जिससे न केवल उसकी आर्थिक पहुँच बढ़ी है, बल्कि उसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मानक–निर्माण की अपनी क्षमता भी सुदृ

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

ढ़ की है। '**String of Pearls**' रणनीति, चाहे औपचारिक रूप से स्वीकार न की गई हो, वस्तुतः हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री, वाणिज्यिक और सैन्य उपस्थिति को प्रतिबिंबित करती है। ग्वादर, हम्बनटोटा, चिटगाँव, क्यौकफ्यू, जिबूती और मालदीव जैसे स्थलों पर चीन की सक्रियता इस बात का संकेत है कि वह समुद्री मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं पर दीर्घकालिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता है।

दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, 'नाइन–डैश लाइन' का एकतरफा दावा और अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय की अवहेलना यह दर्शाती है कि चीन, एक उभरती महाशक्ति होने के बावजूद, नियम–आधारित समुद्री व्यवस्था को चुनौती देने से नहीं हिचकता। यह प्रवृत्ति न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न करती है, बल्कि वैश्विक समुद्री कानून और नौवहन की स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं को भी कमजोर करती है।

भारत के दृष्टिकोण से, हिंद–प्रशांत में चीन की यह समग्र और आक्रामक उपस्थिति एक प्रकार के रणनीतिक घेरे (Strategic Encirclement) के रूप में उभरती है। परिणामस्वरूप, भारत की विदेश और सुरक्षा नीति में स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है—जिसमें Act East Policy, SAGAR सिद्धांत, इंडो–पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, क्वाड सहभागिता और समुद्री साझेदारियों का सुदृढ़ीकरण शामिल है। भारत ने दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और नियम–आधारित व्यवस्था के समर्थन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार के एकतरफा विस्तारवाद का विरोध करता है।

अंततः, हिंद–प्रशांत में चीन का विस्तारवाद इस क्षेत्र की भू–राजनीति का केंद्रीय निर्धारक बन चुका है। भारत के लिए चुनौती केवल चीन की सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक, डिजिटल और समुद्री बहु–आयामी उपस्थिति है। यदि भारत अपनी समुद्री क्षमता, डिजिटल संप्रभुता, अवसंरचना विकास और समान विचारधारा वाले देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को एकीकृत ढंग से आगे बढ़ाता है, तो वह न केवल इस चुनौती का प्रभावी सामना कर सकता है, बल्कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर, समावेशी और नियम–आधारित व्यवस्था के निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में, यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति–संघर्ष अब केवल पारंपरिक सैन्य प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आर्थिक निर्भरता, कर्ज, अवसंरचना, डेटा, समुद्री मार्गों और संस्थागत प्रभाव के क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुका है। चीन की रणनीति इस 'समेकित शक्ति' (Comprehensive Power) दृष्टिकोण का उदाहरण है, जबकि भारत की प्रतिक्रिया 'रणनीतिक लचीलापन' और 'संतुलित बहुपक्षवाद' पर आधारित दिखाई देती है।

Reference:

1. **Gokhale, Vijay**, *Why Taiwan Should Matter to India*, The New Indian Express, New Delhi, May 19, 2025.
Available at: https://www.newindianexpress.com
2. **Pandey, V.; Shekhar, D.; Kumar, S.**, *Strengthening the U.S.–India Subsea Cable Agenda*, The Hindu, New Delhi, June 3, 2025.
Available at:

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/strengthening-the-us-india-subsea-cable-agenda/article69649909.ece
3. **Yu, Jinghao**, *Securing Submarine Cables: A Critical Imperative for Indo-Pacific Stability*, The Diplomat, July 20, 2024.
Available at:
https://thediplomat.com/2024/07/securing-submarine-cables-a-critical-imperative-for-indo-pacific-stability/
4. **Sharan, Harsh Vardhan; Sinha, H. K.**, *Hind–Prashant Kshetra Mein Bhartiya Samudrik Ranniti* (in Hindi), Raj Publications, New Delhi, 2019.
5. **United Nations**, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, United Nations, New York, 1982.
Available at:
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf